

Development of Education in Modern India

(आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास)

- Higher Education was limited to the study of classical Sanskrit, Arabian and Persian at the time of establishment of British Empire in Bengal. Native languages were neglected.
- बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना के समय उच्च शिक्षा संस्कृत, अरबी तथा फारसी के अध्ययन तक ही सीमित थी। देशी भाषा का प्रयोग नगण्य था।
- British Government was almost negligibly interested for the development of Education.
- ब्रिटिश सरकार की शिक्षा के विकास में कोई रुचि नहीं थी।
- Warren Hastings established Calcutta Madarsa in 1781. Sir William Jones founded 'Asiatic Society of Bengal' in 1784 at Calcutta and Jonathan Duncan, Resident of Varanasi started a Sanskrit college at Varanasi in 1792.
- वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' की स्थापना की और वाराणसी के Resident जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया।
- The idea of opening schools for English learning at first stroke to the mind of Charles Grant. Grant made an unsuccessful effort to convince the House of Commons & the Court of Directors.
- पहली बार अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूल खोलने का विचार चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में आया। ग्रांट ने हाउस ऑफ कॉमन्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समझाने का असफल प्रयास किया।
- Christian Missionaries took the responsibility of this task to complete in Madras and Bengal. These Missionary Schools were established with government aid.
- ईसाई मिशनरियों ने मद्रास और बंगाल में इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। ये मिशनरी स्कूल सरकारी सहायता से स्थापित किए गए।
- William Kerry, a cobbler by profession and his friends opened schools without aid of government in India. They published the translation of Bible in Bengali.
- पेशे से मोची विलियम केरी और उसके मित्रों ने भारत में सरकार की सहायता के बिना स्कूल खोले। उन्होंने बंगाली में बाइबिल का अनुवाद प्रकाशित किया।
- Charter Act of 1813 proclaimed that company should suggest the measures for entry of applied knowledge for religious & moral progress. It was ordered that at least a sum of rupees one lac should be separated annually and it should be invested in education..

- 1813 के चार्टर अधिनियम ने घोषणा की कि कंपनी को व्यावहारिक ज्ञान, धार्मिक और नैतिक विकास के लिए सुझाव देना चाहिए। यह आदेश दिया गया कि सालाना कम से कम एक लाख रुपये अलग करके शिक्षा में निवेश किया जाए।
- In 1823, a committee on public education was appointed in Bengal and then steps were taken to start a Sanskrit College at Calcutta.
- 1823 में बंगाल में सार्वजनिक शिक्षा पर एक समिति नियुक्त की गई और फिर कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज शुरू करने के लिए कदम उठाए गए।
- Public Education Committee was spending its money in publishing the Sanskrit, Arabian and Persian books and carrying Sanskrit College and Madarsa. On the other hand, Missionaries started schools and colleges for western type of education with aid to liberal Indians and established 'School Book Society' for selling of books'.
- लोक शिक्षा समिति संस्कृत, अरबी और फारसी पुस्तकों के प्रकाशन और संस्कृत कॉलेज और मदरसा चलाने में धन खर्च कर रही थी। दूसरी ओर मिशनरियों ने उदार भारतीयों की सहायता से पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर स्कूल और कॉलेज शुरू किए और किताबों की बिक्री के लिए 'स्कूल बुक सोसाइटी' की स्थापना की।
- Very soon, Modern thoughts influenced Public Education Committee too. Gradually it split into Orientalists and Anglicists during the time of Lord William Bentinck.
- शीघ्र ही आधुनिक विचारों ने लोक शिक्षा समिति को भी प्रभावित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में यह धीरे-धीरे प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों के बीच विभाजित हो गया।
- Anglicists wanted that money from Public Fund should be spent for the promotion of modern western studies. Naturally, this could benefit only a limited number of students, but they claimed that finally this knowledge would reach the people through Native Literature. This was the famous downward Filtration Theory, which Anglicists advocated.
- आंग्लवादी चाहते थे कि लोक निधि से प्राप्त धन को आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाए। स्वाभाविक रूप से, यह केवल सीमित संख्या में छात्रों को लाभान्वित कर सकता था, लेकिन उनका दावा था कि अंततः यह ज्ञान देशी साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। यह प्रसिद्ध अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था, जिसका आंग्लवादियों ने समर्थन किया था।
- Anglicists got strength with the appointment of famous missionaries Alexander Duff in Public Education Committee.
- लोक शिक्षा समिति में प्रसिद्ध मिशनरी एलेक्जेंडर डफ की नियुक्ति से आंग्लवादियों को बल मिला।
- This group triumphed firstly with the establishment of Medical College at Calcutta in 1835 by Lord William Bentinck. Orientalists finally got defeated with the appointment of new law member, Macaulay as the president of the committee.

- इस समूह की जीत सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ हुई। समिति के अध्यक्ष के रूप में नए विधि सदस्य मैकाले की नियुक्ति के साथ प्राच्यवादी अंततः हार गए।
- Macaulay considered oriental learning completely inferior than European Learning. Macaulay said, "One bookshelf of European library equals all the learning of the East." On 7 March 1835, the council decided to spend money of public fund for English Education.
- मैकाले ने प्राच्य शिक्षा को यूरोपीय शिक्षा से पूरी तरह से इन्फीरियर माना। मैकाले ने कहा, "यूरोपीय पुस्तकालय का एक बुकशेल्फ़ पूर्व की सभी शिक्षाओं के बराबर है।" 7 मार्च, 1835 को परिषद ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए लोक निधि का धन खर्च करने का फैसला किया।
- During the tenure of Lord Harding, a rule was made to fulfill vacancies. According to it, public jobs had to be filled by open competition conducted by Education Council where knowledge of English was preferred. Thus, English education was made the hall-ticket for higher posts available for Indians which finally assured the progress of English.
- लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रिक्तियों को भरने का नियम बनाया गया था। इसके अनुसार, शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता से सरकारी नौकरियों को भरना था जहाँ अंग्रेजी के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी। इस प्रकार, भारतीयों के लिए उपलब्ध उच्च पदों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को हॉल-टिकट बना दिया गया, जिसने अंततः अंग्रेजी की प्रगति को सुनिश्चित किया।
- Charles Wood Dispatch of 1854 (Wood was the president of Board of Control) put the foundation on which the education system of British India developed. This was called Magna-Carta of English education in India.
- 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच (वुड बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल के अध्यक्ष थे) ने वह नींव रखी जिस पर भारत की शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता था।
- Main Virtue of Wood's Dispatch was a systematically arranged education system from lowest to higher stage. Primary schools, Higher Schools, all were linked to higher stage. A regular System of scholarship for meritorious students for advance studies was introduced. There was a provision of government aid for the educational institutions established by personal efforts.
- वुड्स डिस्पैच की मुख्य विशेषता थी - निम्नतम से उच्च स्तर तक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली। प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, सभी को उच्च स्तर से जोड़ा गया। मेधावी छात्रों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की एक नियमित प्रणाली शुरू की गई थी। व्यक्तिगत प्रयासों से स्थापित शिक्षण संस्थानों के लिए सरकारी सहायता का प्रावधान था।
- To meet these objectives, a special department of education had to be opened in every state. To formulate higher education, a university in every presidency was proposed.

- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य में एक विशेष शिक्षा विभाग खोलना था। उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रेसीडेंसी में एक विश्वविद्यालय प्रस्तावित था।
- Woman Education, promotion of Indian language in education and teachers' training were facilitated.
- नारी शिक्षा, शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया।
- Every district had to have the schools and it was said that Indian languages should be medium of education.
- हर जिले में स्कूल और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम होना प्रस्तावित था।
- Lord Dalhousie executed the policy declared in this dispatch without delay. Department of Public Education was established in every province. The first university of India established at Calcutta in 1857 and four new universities started in Bombay, Madras, Lahore and Allahabad between 1857 & 1887.
- लार्ड डलहौजी ने वुड्स डिस्पैच में घोषित नीति को बिना देर किए क्रियान्वित किया। शिक्षा विभाग प्रत्येक प्रांत में स्थापित किया गया। 1857 में भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता में और 1857 से 1887 के बीच बॉम्बे, मद्रास, लाहौर और इलाहाबाद में चार नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

1. Hunter Education Commission, 1882

हंटर शिक्षा आयोग, 1882

- W.W. Hunter Commission was appointed to review the progress in education after 1854. It had to constrain itself only for primary and secondary education inspection, not that of universities-
- 1854 के बाद शिक्षा में प्रगति की समीक्षा के लिए डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था, विश्वविद्यालयों के नहीं-
- इसने निम्नलिखित उपाय सुझाए-
- 1. Government should care for improvement and development of primary education. This education should be in local language and useful subjects. Personal initiatives should be welcomed. Primary education should be given under newly established District and Town Board for which they could impose taxes.
- 1. सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में होनी चाहिए। व्यक्तिगत पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। नए स्थापित जिला एवं नगर बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिस पर वे कर लगा सकें।

- 2. Secondary education should comprise of two parts; one with literary education and other with professional education.
- 2. माध्यमिक शिक्षा में दो भाग होने चाहिए; एक साहित्यिक शिक्षा के साथ और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा के साथ।
- 3. Government should separate itself from secondary and college education.
- 3. सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से खुद को अलग करना चाहिए।
- 4. The commission recommended to enhance women education.
- 4. आयोग ने महिला शिक्षा को बढ़ाने की सिफारिश की।

2. Indian University Act, 1904

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904

- Curzon appointed a commission under Sir Thomas Raleigh on whose recommendation Indian University Act-1904 was passed.
 - कर्जन ने सर थॉमस रैले के अधीन एक आयोग नियुक्त किया जिसकी सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया।
 - Main changes incorporated were:
 - शामिल किए गए मुख्य परिवर्तन थे:
1. Universities should manage the appointments of professors and lecturers and take burden of teaching to students on them.
 1. विश्वविद्यालयों को प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की नियुक्तियों का प्रबंधन करना चाहिए और छात्रों के शिक्षण का बोझ उठाना चाहिए।
 2. Number of fellows of university should be between 50 to 100 with a tenure of 6 years.
 2. विश्वविद्यालय के अध्येताओं की संख्या 6 वर्ष के कार्यकाल के साथ 50 से 100 के बीच होनी चाहिए।
 3. Fellows must be government appointees.
 3. अध्येता सरकारी नियुक्त होने चाहिए।
 4. Government control on universities increased and veto awarded to proposal passed by senate.
 4. विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा और सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को वीटो दिया गया।

5. Non government colleges kept under stringent government control and terms of affiliation to universities were made tough.
5. गैर सरकारी कॉलेजों को कड़े सरकारी नियंत्रण में रखा गया और विश्वविद्यालयों से संबद्धता की शर्तों को सख्त बनाया गया।
6. Governor General was authorized to decide the territorial limit of universities.
6. गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमा तय करने का अधिकार था।
 - In 1917, Sadler Commission accepted the fact that because of the Act of 1904, 'Indian universities became completely government universities in the world.'
 - 1917 में, सैडलर आयोग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 1904 के अधिनियम के कारण, 'भारतीय विश्वविद्यालय पूरी तरह से सरकारी विश्वविद्यालय बन गए।'
 - Government did not accept the principle of compulsory education by the proposal of February 21, 1913 but accepted the policy to eradicate illiteracy. It inspired the provincial governments that they should arrange free education to the poor and more backward class of society.
 - सरकार ने 21 फरवरी, 1913 के प्रस्ताव द्वारा अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को नहीं, बल्कि निरक्षरता उन्मूलन की नीति को स्वीकार किया। इसने प्रांतीय सरकारों को प्रेरित किया कि वे समाज के गरीब और अधिक पिछड़े वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करें।

3. Sadler University Commission, 1917

सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917

- It included two Indian member- Dr. Ashutosh Mukherjee and Jiyauddin Ahmed. Vice-chancellor from University of Leeds. Mr. E. Sadler was presiding it. Commission viewed that to reform the university education, secondary education should be reformed.
- इसमें दो भारतीय सदस्य- डॉ. आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद शामिल थे। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ई. सैडलर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आयोग का विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए।
- School education should be of 12 years. Suggested the board for secondary and post secondary education.
- स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए बोर्ड का सुझाव दिया।
- Three year's education should be for the bachelor degree.
- स्नातक की डिग्री के लिए तीन साल की शिक्षा होनी चाहिए।

- In place of old affiliated universities, where colleges were far and wide, unitary residential teaching and autonomous institutions should be constituted.
- पुराने संबद्ध विश्वविद्यालयों के स्थान पर जहां कॉलेज दूर थे, एकात्मक आवासीय शिक्षण और स्वायत्त संस्थानों का गठन किया जाना चाहिए।
- There should be expansion of facilities for women education. A special board should be constructed in University of Calcutta for women education.
- महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक विशेष बोर्ड का निर्माण किया जाना चाहिए।
- Plenty of facilities should be provided for teachers training.
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भरपूर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- Universities should arrange the syllabus in applied sciences and technologies.
- विश्वविद्यालयों को व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए।

As per the, Indian Government Act, 1919, Department of Education was given under the control of publically elected minister. Central aid for education was ceased.

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अनुसार, शिक्षा विभाग को सार्वजनिक रूप से निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में दिया गया था। शिक्षा के लिए केंद्रीय सहायता बंद कर दी गई थी।

4. Hartong Committee, 1929

हार्टोंग समिति, 1929

An assistance committee under Sir Phillip Hartog was formed, which recommended:

सर फिलिप हार्टोंग के अधीन एक सहायता समिति नियुक्त की, जिसने सिफारिश की:

1. It emphasized the national importance of primary education.
1. इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया।
2. Student with rural tendencies should be stopped at middle school level. They should be taught in professional and industrial education.
2. ग्रामीण प्रवृत्ति वाले छात्रों को माध्यमिक विद्यालय स्तर पर रोका जाए। उन्हें पेशेवर और औद्योगिक शिक्षा पढ़ाया जाना चाहिए।
3. Universities should only enter the eligible students.

3. विश्वविद्यालयों को केवल पात्र छात्रों को ही प्रवेश देना चाहिए।

5. Wardha Education Commission 1937

वर्धा शिक्षा आयोग 1937

- Many articles written by Gandhiji on education in Harijan were combined with the plan on education presented by him in the All India Education Conference held in Wardha in 1937. The Wardha plan was presented in which the following were the main points-
 - गाँधीजी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे अनेक लेखों को 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की। वर्धा योजना प्रस्तुत की जिसमें निम्न मुख्य बातें थी-
1. There should be a system of free and compulsory education for the children of seven to fourteen years.
 1. सात से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।
 2. The medium of education should be the mother tongue so that the student can become self-reliant.
 2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके।
 3. The student should get vocational education according to their interest.
 3. छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले।

This plan could not be implemented due to World War II.

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी।

6. Sargent Plan 1944

सार्जेण्ट योजना 1944

- In 1944, the Education Advisor to the Government of India, Sir John Sargent, presented an important and detailed plan on education whose recommendations were as follows –
- 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेण्ट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें निम्न थीं-
- Elementary schools, middle and high schools should be established in the country.
- देश में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय स्थापित किये जायें।

1. Comprehensive free and compulsory education should be arranged for boys and girls up to the age of 6-11 years.
1. 6-11 वर्ष तक के बाल-बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. Six years of education should be arranged for the age group of 11 to 17 years.
2. 11 से 17 वर्ष की आयु तक के लिए छः वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
3. There will be **two types** of higher schools –
3. उच्च विद्यालय **दो प्रकार** के होंगे -
 - (i) Academic (ii) Technical and Vocational
 - (i) विद्या विषयक (ii) प्राविधिक और व्यावसायिक

7. Radhakrishnan Commission, 1948-49

राधाकृष्ण आयोग, 1948-49

The main recommendations were-

मुख्य सिफारिशें थीं-

1. Pre university education should be of 12 years.
1. विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए।
2. Three objectives of higher education: General education, Moral education and professional education.
2. उच्च शिक्षा के तीन उद्देश्य: सामान्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा।
3. No need of graduation for administrative services.
3. प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक की कोई आवश्यकता नहीं है।
4. There should be a University grants commission; it was constituted in 1953. Education should be included in concurrent list.
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होना चाहिए। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल होना चाहिए।